गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 260
दि. 21.01.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड बना अमेरिका का हिस्सा? ट्रंप ने जारी किया नया नक्शा

(जीएनएस)।

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही वैश्विक राजनीति में एक अभूतपूर्व भूचाल आ गया है। ट्रंप ने हाल ही में एक नया विवादित मानचित्र जारी किया है, जिसमें कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। यह कदम न केवल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की हालिया चीन यात्रा के प्रति ट्रंप की तीखी नाराजगी को भी दशार्ता है।

इसके साथ ही, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के निजी संदेशों को सार्वजनिक करना ट्रंप की उस आक्रामक 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का हिस्सा है, जिसने पूरी दुनिया को युद्ध और अस्थिरता की कगार पर खड़ा कर दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साझा की गई ओवल ऑफिस की तस्वीर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़ा विवाद बन गई है। इस तस्वीर में कीर स्टार्मर और इमैनुएल मैक्रों जैसे नाटो नेताओं की उपस्थिति में पीछे टंगे नक्शे पर ग्रीनलैंड को अमेरिकी ध्वज के रंगों में रंगा गया है। यह न केवल डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान माना जा रहा है, बल्कि यूरोपीय सहयोगियों की संप्रभुता पर भी एक तीखा कटाक्ष है। ट्रंप का यह 'नक्शा विवाद' दशार्ता है कि वे पारंपरिक राजनयिक मर्यादाओं के बजाय आक्रामक राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दे रहे हैं। रणनीतिक रूप से, यह नाटो देशों को यह संदेश देने की कोशिश है कि अमेरिका अब वैश्विक सीमाओं को अपनी सुरक्षा और हितों के अनुसार फिर से परिभाषित करने में संकोच नहीं करेगा। इसने सहयोगियों के बीच भरोसे की कमी और भविष्य के

संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन पर अमेरिकी झंडा

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साझा की गई 'ग्रीनलैंड 2026' की तस्वीर केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि उनके "अमेरिका फर्स्ट" एजेंडे का एक आक्रामक विस्तार है। इस तस्वीर में ट्रंप, जेडी वेंस और मार्को रुबियो के साथ ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन पर अमेरिकी झंडा गाड़ते दिख रहे हैं, जो सीधे तौर पर डेनमार्क की संप्रभुता को चुनौती देता है।

ट्रंप का तर्क है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए ग्रीनलैंड का अमेरिका के पास होना रणनीतिक रूप से अनिवार्य है। 2026 की समय-सीमा तय करके उन्होंने यह संकेत दिया है कि वे इसे केवल एक विचार नहीं, बल्कि अपने कार्यकाल का एक प्रमुख भू-राजनीतिक लक्ष्य मानते हैं। यह कदम नाटो सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ा सकता है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की कोशिश है।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का निजी संदेश किया शेयर

वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का एक निजी संदेश साझा किया है, जो ग्रीनलैंड विवाद के बीच वैश्विक कूटनीति की जटिलता को उजागर करता है। इस संदेश में मैक्रों ने सीरिया और ईरान जैसे मुद्दों पर सहयोग की बात तो की, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के कदमों पर अपनी स्पष्ट उलझन व्यक्त की है।

मैक्रों ने इस गतिरोध को सुलझाने और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए पेरिस में एक ऋ बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने इस बैठक के हाशिये पर यूक्रेन, रूस और विशेष रूप से डेनमार्क के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की योजना साझा की, ताकि ग्रीनलैंड जैसे संवेदनशील विषयों पर संवाद हो सके। ट्रंप द्वारा इस निजी बातचीत को सार्वजनिक करना उनके आक्रामक कूटनीतिक अंदाज को दशार्ता है, जिससे यूरोपीय सहयोगियों के साथ तनाव और बढ़ सकता है।

ऑनलाइन निवारण का जनवरी महीने का राज्य स्तरीय 'स्वागत' गुरुवार, 22 जनवरी को आयोजित होगा

गांधीनगर, 20 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हर महीने आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी-2026 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) गुरुवार, 22 जनवरी को आयोजित होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2003 से शुरू हुए स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत हर महीने के चौथे गुरुवार को राज्य स्तरीय 'स्वागत' का आयोजन किया जाता है।

तदनुसार, जनवरी-2026 के राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम के लिए नागरिक अपना अभ्यावेदन गुरुवार, 22 जनवरी की सुबह 8.00 से 11.00 बजे के दौरान मुख्यमंत्री की जनसंपर्क इकाई, स्वर्णिम संकुल-2, गांधीनगर में व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री गुरुवार दोपहर बाद इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' में स्वयं मौजूद रहकर नागरिकों की शिकायतें सुनेंगे।

प्रधानमंत्री ने भारत के वस्त्र क्षेत्र के विकास पर एक लेख साझा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा लिखित एक लेख साझा किया है। यह लेख भारत के वस्त्र उद्योग के एक पारंपरिक उद्योग से एक शक्तिशाली, रोजगार सृजन करने वाले और लोक-केंद्रित विकास के इंजन के रूप में उभरने की कहानी वर्णित करता है, जो आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को दशार्ता है। इसमें रेखांकित किया गया है कि पीएम मित्र पार्क, पीएलआई योजनाएं और नए मुक्त व्यापार समझौते जैसी पहलें रोजगार की अगली लहर सृजित कर रही हैं। पीएमओ इसे पोस्ट किया; केंद्रीय मंत्री श्री @girirajsinghbjp ने इस लेख में भारत के वस्त्र क्षेत्र के एक पारंपरिक उद्योग से एक शक्तिशाली, रोजगार सृजन करने वाले, लोक-केंद्रित विकास के इंजन के रूप में उभरने की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

यूपी: सीएम योगी बोले- पार्टी को नई ऊर्जा व दिशा देंगे नितिन नबीन...उत्तर प्रदेश को भी मिलता रहेगा मार्गदर्शन

लखनऊ , (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर बधाई दी। सीएम ने उनके नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी तथा उत्तर प्रदेश को भी निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और उन्हें बधाई के साथ उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। सीएम योगी ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ भेंट किया और अपने सोशल मीडिया एकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट करके भी उन्हें पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि "आपके कुशल नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और दूरदर्शिता से पार्टी को नई ऊर्जा-दिशा मिलेगी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती प्राप्त होगी।" सीएम ने आशा जताई कि उत्तर प्रदेश को भी आपका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में आप अंत्योदय के पथ पर चलते हुए अपनी निष्ठा व समर्पण से संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे एवं सभी कर्मठ कार्यकताओं में 'राष्ट्र प्रथम' के भाव को और सुदृढ़ करेंगे। आपके उज्ज्वल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं।

असम : 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत 213.9 करोड़ रुपये जारी किए

केंद्र सरकार ने असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अप्रतिबंधित अनुदान के रूप में ₹213.9 करोड़ जारी किए हैं। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त है। यह राशि राज्य भर में सभी 2,192 पात्र ग्राम पंचायतों, 182 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 27 पात्र जिला परिषदों के लिए जारी की गई है।

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त वर्ष के अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किए जाते हैं।

डाक विभाग ने भारत भर में 887 एटीएम सक्रिय करके अपने एटीएम ढांचे का आधुनिकीकरण किया है

बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने

की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, डाक विभाग ने देश भर में अपने एटीएम बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया है। विभिन्न डाकघरों में स्थापित ये 887 एटीएम नागरिकों को उनके घरों के पास ही आवश्यक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने में मदद कर रहे हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लाभदायक है, जिससे डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के सरकार के दृष्टिकोण को बल मिलता है।

इन एटीएम के माध्यम से ग्राहक

महत्वपूर्ण फेज में पहुंचा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम

(जीएनएस)। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर ने अब विद्युतीकरण के एक महत्वपूर्ण फेज में एंट्री कर चुका है। इसके तहत कई हिस्सों में ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (OHE) के मास्ट लगाए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रगति को 'मेक इन इंडिया' पहल से जोड़ा है, जो भारत की पहली हाई-स्पीड रेल प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।

यह 508 किलोमीटर लंबी मुंबई-अहमदाबाद परियोजना महाराष्ट्र और गुजरात के बीच 12 स्टेशनों को जोड़ेगी। इसका लक्ष्य देश का पहला समर्पित हाई-स्पीड रेल मार्ग तैयार करना है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए डिजाइन किया गया यह कॉरिडोर, वाणिज्यिक सेवाएं शुरू होने पर सुरक्षित, स्थिर और कुशल ट्रेन संचालन सुनिश्चित करेगा।

रेल मंत्री ने वीडियो शेयर कर दिया अपडेट

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर एक अपडेट साझा करते हुए लिखा था: ""मेक इन इंडिया" बुलेट ट्रेन परियोजना को शक्ति दे रहा है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर ओवरहेड विद्युतीकरण मास्ट लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।" यह भारत की पहली हाई-स्पीड रेल प्रणाली

में 'मेक इन इंडिया' के महत्व पर जोर देता है।

क्यों बेदह अहम हैं बुलेट ट्रेन प्रोजक्ट का ये फेज?

वायडक्ट पर ओएचई मास्ट का इंस्टॉलेशन बुलेट ट्रेनों को ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रेलवे के अनुसार, ये इस्पात संरचनाएं आवश्यक ट्रैक्शन प्रणाली का हिस्सा हैं, जो मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति देंगी।

प्रोजेक्ट में कुल ये 12 स्टेशन शामिल हैं- इस प्रोजेक्ट में कुल 12 स्टेशन शामिल हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। मार्ग के कई खंड ऊंचे वायडक्ट पर स्थित हैं, जहां स्पष्ट और सुरक्षित संचालन के लिए ओएचई मास्ट जमीन से काफी ऊंचाई पर लगाए जा रहे हैं।

OHI मास्क लगाए जाएंगे

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ 9.5 मीटर से 14.5 मीटर ऊंचे 20,000 से अधिक ओएचई मास्ट लगाने की योजना है। ये मास्ट पूर्ण 2x25 kV ट्रैक्शन प्रणाली को सहारा देंगे, जिसमें ओवरहेड संपर्क तार, अर्थिंग हार्डवेयर, फिटिंग और एक्सेसरीज शामिल हैं, जो हाई-स्पीड ट्रेनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करेंगे।

भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति बैठक की दिल्ली में अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक आज दिनांक 20 जनवरी, 2026 को तीस्ता सभागार, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी द्वारा की गई। बैठक में संसद के दोनों सदनों के माननीय सांसद श्री मिथलेश कुमार, श्रीमती माया नारोलिया और श्रीमती कमलेश जांगड़े और हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वान शामिल हुए। बैठक में मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रभारियों ने भी समिति की बैठक में भाग लिया।

समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष, माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री महोदय ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हिंदी भाषा

एक बेहतर संपर्क का माध्यम है और सभी को विशेष तौर पर मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मंत्रालय की विषय वस्तु और मंत्रालय की योजनाओं को सरलता से आम जनता तक पहुंचाया जा सके तथा आम जनता इसे भली भांति समझ सके। भाषा की जटिलता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हमें सरल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर उनके व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं। हमें अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के अधिकारी हिंदी में हस्ताक्षर से शुरूआत करके महीने में एक बार कम से कम एक टिप्पणी हिंदी में करें और धीरे-धीरे हिंदी में कार्य करने की आदत डालें।

समिति के माननीय सदस्यों ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिंदी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक के अंत में माननीय सचिव महोदय ने समिति के सदस्यों का धन्यवाद देते हुए समिति को यह आश्वासन दिया कि वे सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर यथोचित कार्रवाई करेंगे तथा मंत्रालय के कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

'हर हिन्दू करे 4 बच्चे पैदा', बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री का नया फामूर्ला, जाति-धर्म पर भी कही बड़ी बात

(जीएनएस)।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर चचाओं में हैं। वजह है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आयोजित एक भव्य धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम के दौरान उनका बयान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक ऐसा संबोधन दिया है, जिसने पूरे देश के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।

'हनुमंत कथा' के मंच से बोलते हुए उन्होंने न केवल हिंदू एकता का आह्वान किया, बल्कि जातिवाद, जनसंख्या संतुलन और राष्ट्रवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी बेबाक राय रखी। उनके बयानों के वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं। उनके इस वीडियो से एक नई बहस छिड़ गई है।

धीरेंद्र शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि हिंदू समाज अपनी आंतरिक कड़ियों को नहीं जोड़ता है, तो भविष्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने तिरंगे के मान-सम्मान और देश की अखंडता को लेकर भी ऐसी टिप्पणियां कीं, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का मुख्य केंद्र बन गई हैं।

बांदा के मंच से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने देश की एकता पर प्रहार करने वाली ताकतों को निशाने पर

लिया। उन्होंने कहा, 'जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया, उस दिन न तो शर्मा बचेंगे, न वर्मा बचेंगे और न ही कोई अन्य जाति बचेगी।' उन्होंने बांग्लादेश की हालिया घटनाओं का उदाहरण देते हुए समाज को आगाह किया कि बंटवारा हमेशा विनाश लाता है। शास्त्री ने जोर देकर कहा कि अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तो किसी भी वर्ग या जाति की सुरक्षा संभव नहीं होगी।

जातिवाद पर प्रहार, 'शर्मा-वर्मा नहीं, केवल हिंदू'

कथावाचक ने हिंदू समाज के भीतर गहरी जड़ों तक फैले जातिवाद को समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि लोग खुद को जातियों (अगड़ा-पिछड़ा) में बांटकर अपनी असली ताकत भूल रहे हैं।

धीरेंद्र शास्त्री के अनुसार, अन्य समुदायों में आपसी मतभेद होने के बावजूद वे धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं, लेकिन हिंदू समाज अभी भी जातियों में उलझा हुआ है। उन्होंने आह्वान किया कि व्यक्ति की पहली और एकमात्र पहचान 'हिंदू' होनी चाहिए, न कि उसकी जाति।

'2 बच्चे घर के लिए, 2 राष्ट्र के लिए'

जनसंख्या के मुद्दे पर धीरेंद्र शास्त्री ने एक नया फामूर्ला पेश किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अपनी घटती संख्या को लेकर गंभीर होना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक हिंदू परिवार को कम से कम चार बच्चे पैदा करने का सुझाव दिया।

उन्होंने विस्तार से बताया कि इनमें से दो बच्चे परिवार संभालें, एक बच्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (फर) को और एक बच्चा हिंदू राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा तभी संभव है जब संख्या बल मजबूत होगा।

शिक्षा पद्धति और 'ग' से गणेश बनाम गधा

अपने संबोधन में उन्होंने आधुनिक शिक्षा पद्धति पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले स्कूलों में 'ग' से गणेश पढ़ाया जाता था जिससे बच्चों में संस्कार आते थे, लेकिन अब 'ग' से गधा पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने इसे एक साजिश बताते हुए कहा कि बच्चों को अपनी संस्कृति और वेदों से दूर किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए वे स्वयं 'गुरुकुल' और कैंसर अस्पताल जैसी संस्थाएं बना रहे हैं।

सम्पादकीय

गठबंधन की विश्वसनीयता से जुड़ी है महाराष्ट्र की राजनीति

मेयर की वुसा से बड़ा है महाराष्ट्र में गठबंधन का भविष्य, मुंबई की राजनीति केवल मेयर पद तक सीमित नहीं है। यह महाराष्ट्र की सत्ता, भविष्य की चुनावी दिशा और गठबंधन की विश्वसनीयता से जुड़ी हुईं है। एकनाथ शिदे और भाजपा दोनों के लिए यह समय संयम, संवाद और समझदारी का है। मुंबई की सत्ता और संयम की राजनीति, मेयर की कुर्सी से बड़ा है गठबंधन का भविष्य मुंबई महानगरपालिका के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि प्रतीकों, भावनाओं, स्मृतियों और सत्ता-संतुलन की जटिल बुनावट है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भाजपा का सबसे बड़ी पाटा बनकर उभरना ऐतिहासिक है। यह संकेत देता है कि शहरी मतदाता ने इस बार परंपरागत राजनीति से हटकर निर्णय लिया है। लेकिन नतीजों के तुरंत बाद जिस तरह मेयर पद को लेकर खींचतान शुरू हुईं, उसने जीत की चमक को धुंधला कर दिया है और गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा के 89 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पाटा बनने के बाद स्वाभाविक रूप से यह अपेक्षा बनी कि पहली बार मुंबई को भाजपा का मेयर मिलेगा। दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास 29 पार्षद हैं, जो बहुमत के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसी गणित के सहारे शिदे गुट ने मेयर पद पर ढाईं साल का दावा ठोक दिया है। तर्क दिया जा रहा है कि यह साल शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से मेयर पद शिवसेना के पास होना चाहिए। राजनीति में प्रतीकों का महत्व होता है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन सत्ता संचालन केवल प्रतीकों से नहीं चलता, इसके लिए व्यवहारिकता और दूरर्दशिता की जरूरत होती है। पार्षदों को ताज होटल में शिफ्ट करना, कड़ा पहरा, बंद दरवाजों के पीछे रणनीति बनाना, यह सब दृश्य मुंबई की राजनीति में नया नहीं है, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि अविश्वास की दीवारें ऊंची हो रही हैं। सवाल यह नहीं है कि शिदे गुट अपनी ताकत दिखा रहा है या भाजपा दबाव में है, सवाल यह है कि क्या यह टकराव उस गठबंधन के हित में है, जिसने वुछ समय पहले तमाम मतभेद भुलाकर महाराष्ट्र की सत्ता संभाली थी। पिछले विधानसभा चुनाव और उसके बाद की घटनाओं को अगर याद किया जाए, तो यह साफ दिखता है कि भाजपा ने अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर एकनाथ शिदे को मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय शिवसेना टूट के दौर से गुजर रही थी, संगठन बिखरा हुआ था और शिदे गुट को वैधता और स्थिरता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। भाजपा ने उस वत्त सहयोग का हाथ बढ़ाया, सत्ता साझा की और यह संदेश दिया कि गठबंधन केवल मजबूरी नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी है। आज उसी साझेदारी की परीक्षा मुंबई महानगरपालिका में हो रही है। मुंबई केवल एक नगर निगम नहीं है। यह बजट, प्रभाव और निर्णय क्षमता के लिहाज से एशिया की सबसे ताकतवर नगरपालिकाओं में से एक है। यहां का मेयर पद केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक शत्ति का भी प्रतीक है। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी भी उम्मीदों के सहारे बयानबाजी कर रही है और कांग्रेस अपनी आंतरिक लड़ाई में उलझी हुईं है। लेकिन असली मुकाबला भाजपा और शिदे गुट के बीच है, और इसका असर राज्य की राजनीति पर दूरगामी हो सकता है। शिदे गुट की चिता समझ में आती है। उद्धव ठाकरे की ओर से लगातार 'मराठी अस्मिता' और भावनात्मक राजनीति का कार्ड खेला जा रहा है। ऐसे में शिदे गुट को डर है कि अगर मुंबई में भाजपा का मेयर बनता है, तो शिवसेना की पारंपरिक पहचान और कमजोर हो सकती है। यही डर उन्हें आामक रुख अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन राजनीति में डर के आधार पर लिए गए पैसले अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। व्यवहारिक राजनीति यह कहती है कि गठबंधन में छोटे और बड़े दलों को अपने-अपने दायरे समझने होते हैं। भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मेयर पद का स्वाभाविक दावा है, जबकि शिदे गुट के लिए उपमहापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष जैसे पद भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

कच्छ की सरहद डेयरी में है भारत का प्रथम कैमल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट

- कच्छ की सरहद डेयरी में है भारत का प्रथम कैमल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, ऊँटनी के दूध की राजभोग आइसक्रीम बनाने वाली देश की एक मात्र डेयरी
- सहकार से समृद्धि : सरहद डेयरी ने 900 दूध मंडलियों तथा 31,067 पशुपालकों के बैंक खाते खोले, 438 मंडलियों को माइक्रो एटीएम मिले
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भूकंप के बाद कच्छ की हुई कायापलट, सहकारिता क्षेत्र में सरहद डेयरी लाई सकारात्मक परिवर्तन

गांधीनगर, (जीएनएस)। 26 जनवरी, 2001 को आए विनाशकारी भूकंप ने कच्छ को इस हद तक तबाह किया कि हरेक के मन में प्रश्न था कि कच्छ फिर से उठ खड़ा हो पाएगा या नहीं। हालाँकि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस प्रदेश की ऐसी कायापलट हुई कि कच्छ विकास, आत्मनिर्भरता तथा सहकारी समृद्धि का उत्तम उदाहरण बन गया है। उनके नेतृत्व में कच्छ पर्यटन, कृषि, सहकारिता जैसे क्षेत्रों में अग्रसर जिला बना है। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में कच्छ की विकास यात्रा को और गति मिली है।

उल्लेखनीय है कि भूकंप के बाद कच्छ के सहकारिता क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में 'श्री कच्छ जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ' यानी सरहद डेयरी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। 2009 में श्री वलमजी हुंबल द्वारा स्थापित सरहद डेयरी कच्छ की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है और जिले के पशुपालकों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है।

सरहद डेयरी 80,000 दूध उत्पादकों से प्रतिदिन 5.5 लाख लीटर दूध प्राप्त करती है

सरहद डेयरी 900 से अधिक सहकारी मंडलियों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 80,000 दूध उत्पादकों से लगभग 5.5 लाख लीटर दूध एकत्र करती है। डेयरी में प्रतिदिन 4 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होती है और यहाँ 300 टन क्षमता का पशु आहार (कैटल फीड) प्लांट भी है। इसके अतिरिक्त; डेयरी द्वारा प्रतिदिन 50,000 लीटर आइसक्रीम भी बनाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन 3.38 लाख लीटर प्रतिदिन दर्ज हुआ है। डेयरी द्वारा पशुपालकों को प्रतिदिन अनुमानित 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान सरहद डेयरी ने 1,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक टर्नओवर हासिल किया है, जो वार्षिक 9.09 प्रतिशत की वृद्धि दशार्ता है। सरहद डेयरी हरियाणा, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अमूल के डेयरी प्लांट को भैंस के शुद्ध दूध की आपूर्ति करने में भी अग्रसर है।

सरहद डेयरी में है भारत का प्रथम कैमल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट

कच्छ के रण का सफेद सोना माने जाने वाले ऊँटनी के दूध में भरपूर खाद्य खनिज तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायी हैं और रोगप्रतिकारक शक्ति में वृद्धि करते हैं। भारत का सर्वप्रथम ऊँटनी के दूध को दुर्गंधमुक्त करने का प्रोसेसिंग प्लांट कच्छ में यानी सरहद डेयरी के पास है, जो 16 जनवरी 2019 से कार्यरत है। ऊँटनी के दूध के लिए प्राथमिक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी सरहद डेयरी ने प्राप्त किया है। कच्छ जिले में रापर, नखत्राणा, गढशीशा तथा कोटडा आथमणा; इन चार कलेक्शन केन्द्रों के माध्यम से ऊँटनी के दूध का अमूल पैटर्न के अनुसार कलेक्शन किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान ऊँटनी के दूध का दैनिक संग्रहण 4,754 लीटर हुआ है। ऊँटनी का दूध जमा कराने वाले ऊँटपालकों को वार्षिक 8,72,83,440 रुपए का भुगतान किया गया है, जिससे 350 से अधिक ऊँटपालक परिवारों को लाभ हुआ है।

इसके अतिरिक्त; समग्र भारत में ऊँटनी के दूध की राजभोग फ्लेवर की आइसक्रीम केवल सरहद डेयरी में ही बनाई जाती है। 22 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस आइसक्रीम प्लांट का उद्घाटन किया गया था और इस प्लांट द्वारा केवल एक ही वर्ष में 80 वेराइटी लॉन्च की गई हैं। वर्ष 2024-25 में कुल 24.52 लाख लीटर आइसक्रीम का उत्पादन किया गया और अधिकतम डिसपैच 58,000 लीटर दर्ज हुआ है।

सरहद डेयरी को मिली है वैश्विक पहचान

जनवरी 2022 में गांधीनगर में इंडियन डेयरी एसोसिएशन (आईडीए) कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी; जिसमें सरहद डेयरी ने भाग लिया था, तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (आईडीएफ) द्वारा केरल राज्य के कोच्चिं में विश्व में पहली बार आयोजित रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस 2024 में विश्व में ऊँट तथा ऊँटनी के विषय पर आयोजित एक महत्वपूर्ण सत्र में सरहद डेयरी द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऊँटनी के दूध की प्रोसेसिंग तथा उत्पादों में किए गए उत्कृष्ट कामकाज का विश्व स्तर पर संज्ञान लिया गया।

इसी प्रकार; सरहद डेयरी को 2025 में दुबई में आयोजित विश्व के सबसे बड़े फूड शो 'गल्फ फूड एक्सपो' में भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिली, जहाँ अमूल के स्टॉल पर ऊँटनी के दूध के उत्पादकों ने विशेष आकर्षण जमाया। सरहद डेयरी को उसके प्रशंसनीय कामकाज के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं; जिनमें सामाजिक विकास तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऋडङक्अ अद्द१ि 2014, कच्छ डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए रोटरी क्लब वॉकेशनल एक्सीलेंस अवॉर्ड 2017, एग्रीटेक में उत्कृष्टता के लिए ऋडङक्अ अद्द१ि 2024 तथा टिकाऊ प्रदर्शन के लिए श्ठट ळश की ओर से ग्रीन वर्कप्लेस अवॉर्ड 2025 शामिल हैं।

'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार कर रही है सरहद डेयरी

'सहकार से समृद्धि' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की एक दूरदर्शी पहल है। इस कार्यक्रम अंतर्गत सरहद डेयरी ने कच्छ जिला मध्यस्थ सहकारी (केडीसीसी) बैंक में 900 दूध मंडलियों तथा 31,067 पशुपालकों की बैंक खाते खोलने में सहायता की है। बैंकिंग को अधिक सरल बनाने के लिए किसानों को रुपे कार्ड दिए गए हैं और 438 दूध मंडलियों को माइक्रो एटीएम प्राप्त हुए हैं।

सर्दियों में खो गई चेहरे की चमक? हरी सब्जियों से पाएं स्किन पर निखार-शहनाज हुसैन

आजकल तापमान में गिरावट के साथ ही हवा में ठंडक बढ़ रही है जिसकी वजह से त्वचा शुष्क, बेजान तथा निर्जीव सी दिखने लगती है। ठण्डक आपकी प्रतिरोधक क्षमता के साथ ही आपकी त्वचा तथा बालों पर भी असर करती है। ऐसे में या तो आप लोशन क्रीम, मॉइस्चराइजर बार-बार लगाते रहें और या आप प्रकृतिक तरीकों से अपने शरीर की आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करें जिससे आप प्रकृतिक तौर पर सुन्दर दिखेंगी तथा मौसम का मिजाज आपकी त्वचा, बालों को प्रभावित नहीं कर सकेगा।

सर्दियों के मौसम में प्रकृति हमें पालक, सरसों का साग, मेथी, बथूआ, हरे पत्तों का सलाद सहित ऐसी हरी पते दार सब्जियां प्रदान करती है जिसके सेवन से हमारी त्वचा मौसम की मार को आसानी से झेल सकती है। इन हरी सब्जियों में एंटी आक्सीडेंट विटामिन, मिनरल तथा अन्य पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं जोकि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ सुन्दरता को भी निखारते हैं।

1 -गाजरः सर्दियों में बाजार में लाल रंग की गाजर सामान्यतः मार्केट में मिलती है जबकि बाकी सीजन में नारंगी रंग की गाजर देखने को मिलती है। गाजर विटामिन-सी से भरपूर होती है जिससे शरीर में कॉलाजन की उत्पत्ति होती है जो कि त्वचा को कोमल , मुलायम तथा लचीला बनाती है। गाजर में विद्यमान विटामिन ए से चेहरे पर झुर्रियां रोकने में मदद मिलती है। गाजर को फेस मास्क के रुप में प्रयोग किया जा सकता है।

गाजर को पानी में उबाल कर ठण्डा होने दें तथा ठण्डा होने पर इसे मसल कर बनी लुगदी को चेहरे पर लगाकर थोड़ी देर बाद चेहरे को साफ ताजे पानी से धो डालिए। इससे चेहरे की प्रकृतिक आभा में निखार आएगा। इसके नियमित प्रयोग से कील-मुहांसों तथा काले धब्बों से निजात मिलेगी।

2 खीराखीरे में सौंदर्य मिनरल "सीलिका" विद्यमान होता है जिसकी वजह से त्वचा की रंगत में निखार आता है तथा त्वचा कोमल व मुलायम हो जाती है। खीरा प्राकृतिक टोनर होता है। तैलीय त्वचा के लिए आप खीरे के रस को सीधे त्वचा पर लगाकर 15 मिनट बाद साफ पानी से धो डालें। खीरे के रस तथा गुलाब जल को मिलाकर बने मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद पानी से धो डाले। खीरे के गाढ़े गूदे में दो चम्मच गुलाब जल डालकर बलेंड कर लें तथा इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 30 मिनट बाद ताजे साफ पानी से धो डालें। खीरा अस्ट्रिन्जन्ट होता है तथा टोनिंग और रिफ्रेशिंग के अलावा यह त्वचा के छिद्रों को बंद करता है तथा तैलीयपन को कम करता है खीरे को कद्दूकस करके या खीरे के रस को आंखों के इर्दगिर्द त्वचा पर लगाने से डार्क सर्कल कम होते हैं तथा त्वचा की रंगत में निखार आता है।

खीरा खाने से आपकी स्किन हाइड्रेट रहती हैं। खीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के कारण त्वचा पर झुर्रियां और स्किन रेडनेस की समस्या से भी राहत मिल सकता है।

3 पालक पालक- सेहत का खजाना माना जाता है/ इसका

जादुई असर खाने और लगाने दोनों से मिलता है/ पालक में

फाइबर प्रोटीन विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन.के विद्यमान होता है और इसके अतिरिक्त इसमें आयरन फोलेट और पोटेशियम पाया जाता है /

पालक का फेस मास्क चेहरे की खूबसूरती निखारने में अहम भूमिका अदा करता है / दही और पालक का फेस पैक बनाने के लिए आप पांच पत्तों के हिसाब से तीन चम्मच दही ले सकते हैं।

इन दोनों चीजों को एक साथ मिक्सर में ग्राइंड कर लें। पालक का पेस्ट बनाकर भी दही में मिक्स कर सकते हैं।

इस पेस्ट को कम से कम 10 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा कर रखें।

चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं।

ए.एस.एम.ई ईएफएक्स इंडिया 2026 का समापन हुआ, भारत के प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन मिला

एलआरडी

लखनऊ, 20 जनवरी 2026: ए.एस.एम.ई फाउंडेशन इंडिया (AFI) के राष्ट्रीय इंजीनियरिंग फेस्टिवल, ईएफएक्स इंडिया 2026 का समापन जयपुर में हो गया। तीन दिन चले इस आयोजन में गहन लर्निंग, इनोवेशन और सहयोग देखने को मिला। इस ईवेंट में हैंड्स-ऑन लर्निंग और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए केरल, ओडिशा, दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित 19 राज्यों से इंजीनियरिंग के 700+ स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया।

ईएफएक्स इंडिया 2026 का उद्देश्य इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हैंड्स-ऑन लर्निंग और उद्योग की चुनौतियों के अनुरूप इंटरडिसिप्लिनरी कौशल प्रदान करना तथा वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार करना था। इवेंट में स्टूडेंट्स, शिक्षाविदों और उद्योग के प्रोफेशनल्स को संवाद करने का अवसर मिला तथा इंजीनियरिंग के परिवेश की बदलती जरूरतें सामने आयीं।

इस इवेंट में विकसित होती हुई टेक्नोलॉजी और व्यवहारिक प्रयोग के सत्रों एवं चुनौतियों के माध्यम से इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया। 'रोबोटिक्स इन द एज ऑफ ए.आईः मूविंग फ्रॉम ऑटोमेशन टू ऑटोनॉमी' वर्कशॉप रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर केंद्रित थी। इसने सितंबर 2026 में चेन्नई में आयोजित होने वाले ए.एस.एम.ई इंडिया के एशिया-स्तर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कांग्रेस एंड एक्सपोज़िशनञ (क्टएउए इंडिया 2026) की भूमिका तैयार की।

इस पहल के बारे में ए.एस.एम.ई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट एवं डायरेक्टर, श्री मधुकर शर्मा ने कहा, 'भारत को अगर सर्विस इकोनॉमी से एक ग्लोबल 'प्रोडक्ट नेशन' बनना है, तो हमें 'मेक इन

इंडिया' से आगे सोचकर 'डिजाइन इन इंडिया' की ओर बढ़ना होगा। ए.एस.एम.ई ईएफएक्स इंडिया 2026 इस बदलाव को शुरू करता है। ए.एस.एम.ई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को समर्थ बना रहा है, जो सस्टेनेबल मोबिलिटी से लेकर ऑटोनॉमस सिस्टम तक मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल्स और इनोवेशन के साथ वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने की सोच रखते हैं।'

ए.एस.एम.ई फाउंडेशन इंडिया की डिप्टी डायरेक्टर, सुश्री अवनी मल्होत्रा ने कहा, 'असली इनोवेशन के लिए सोच और विचारों में विविधता रखना जरूरी है। ए.एस.एम.ई फाउंडेशन इंडिया हर स्टूडेंट की इस क्षमता का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'गियर अप एफ.ई.एम.ई' साबित करता है कि महिलाएं डिजाइन इंजीनियरिंग में सबसे आगे रहने की हकदार हैं।'

ईएफएक्स इंडिया 2026 में विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों के अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में अलग-अलग संस्थान विजेता बनकर उभरे। फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (केरल), ञ्छर गोगटे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कर्नाटक), सर एम. विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कर्नाटक), मार एथेनेसियस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (केरल) और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (दिल्ली) जैसे कॉलेजों ने मजबूत टेक्निकल विशेषज्ञता, इनोवेशन और टीम वर्क का प्रदर्शन किया और एक से अधिक प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। उनकी उपलब्धियों से इवेंट में इंजीनियरिंग प्रतिभा की गहराई और प्रतियोगिता की भावना उजागर हुई।

इस ईवेंट के मुख्य आकर्षणों में से एक "गियर अप एफ.ई.एम.ई - व्हेयर हर आईडियाज टेक शेप" था। यह केवल महिलाओं के लिए पेश किया गया इंजीनियरिंग का एक चैलेंज था, जिसका नेतृत्व ए.एस.एम.ई वीमेन इन इंजीनियरिंग ने किया। इस सत्र में चार घंटे का कैड और सिमुलेशन चैलेंज था, जिसमें निर्धारित समय-सीमा में प्रतिभागियों की रचनात्मकता, सटीकता और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स का परीक्षण किया गया।

ईएफएक्स इंडिया 2026 में आईआईटी रोपर, बोईंग, गिसेक एंड डेव्रिएंट और सीमंस एनर्जी इंडिया जैसे संस्थानों व संगठनों से शिक्षाविदों और औद्योगिक प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया, जिससे शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा मिला।

ईएफएक्स इंडिया 2026 के ऑफिशियल स्पॉन्सर गेल और द वेल्डिंग इंस्टीट्यूट (ळहक) इंडिया थे, जिससे स्टूडेंट्स को उद्योग के साथ संपर्क स्थापित करने और प्रायोगिक अनुभव बढ़ाने का मौका मिला।

गेल (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर के चीफ जनरल मैनेजर, श्री संजय चौहान ने कहा कि, 'मैं ई.एफ.एक्स इंडिया 2026 में सहयोग देने के इस अवसर का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर भारत के सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर्स ने ई-'मन-पॉवर्ड व्हीकल चैलेंज जैसी हैंड्स-ऑन प्रतियोगिताओं के माध्यम से सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। केवल महिलाओं के लिए कैड चैलेंज, गियर अप एफ.ई.एम.ई द्वारा डिजाइन, एनालिसिस और इनोवेशन स्किल्स में सुधार हुआ। विविधता और सस्टेनेबल भविष्य की ओर हमारे प्रयास का बढ़ावा मिला। ए.एस.एम.ईप्रतियोगिताओं के माध्यम से मल्टीडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग के साथ रियल-वर्ल्ड प्रोटोटाइप के विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे टीम वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इनोवेशन स्किल्स का विकास होता है। आज के नियोक्ता इन्हीं कौशलों की मांग करते हैं।'

ईएफएक्स इंडिया 2026 का समापन टेक्निकल लर्निंग, इंटरडिसिप्लिनरी कौशल और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने का कौशल प्रदान करके भविष्य के इंजीनियरों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ हुआ, ताकि इंजीनियरिंग डिजाइन और इनोवेशन के वैश्विक केन्द्र के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत बनाया जा सके।

समुद्री खाद्य निर्यात के संवर्द्धन के संबंध में राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ गोलमेज सम्मेलन

समुद्री खाद्य निर्यात के संवर्द्धन के संबंध में राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ मत्स्य पालन गोलमेज सम्मेलन 21 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा

द्विपक्षीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार संपर्क को मजबूत करने का उद्देश्य

(जीएनएस)।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग की ओर से द्विपक्षीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से 21 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में समुद्री खाद्य निर्यात के संवर्द्धन के विषय में राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है । मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन और पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

भारत जलीय कृषि पदार्थों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह मछली और जलीय खाद्य पदार्थों के अग्रणी वैश्विक उत्पादकों में से भी एक है। वर्षों से यह क्षेत्र मुख्य रूप से जीविका संबंधी गतिविधि से विकसित होकर व्यावसायिक रूप से मजबूत, नियातीन्मुख अनुकूल परिवेश के रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसमें मत्स्यपालन, चारा, प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, व्यवस्था संचालन तंत्र और मूल्यवर्धन शामिल हैं। साथ ही यह लाखों छोटे, सीमांत और पारंपरिक मछुआरों तथा किसानों को निरंतर सहयोग प्रदान करता है। लक्षित योजनाओं और सुनियोजित नीतियों की सहायता से भारत आज मछली एवं मत्स्य उत्पादों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। 2024-25 में समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात 16.98 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया जो 62,408 करोड़ रुपये (7.45 बिलियन अमरीकी डॉलर) के बराबर

था। यह भारत के कुल कृषि निर्यात में लगभग 18 प्रतिशत योगदान देता है।

भारत सरकार एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ओशेनिया और लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन के 83 साझेदार देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों की भागीदारी के साथ इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रही है । विदेश मंत्रालय, मत्स्य विभाग, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), एजेंस फ्रांसेज डी डेवलपमेंट (एएफडी), ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनार्बीट (जीआईजेड), बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम (बीओबीपी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। यह सम्मेलन समुद्री खाद्य व्यापार, बाजार तक पहुंच, नियामक सहयोग और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारियों को गहरा करने के उभरते अवसरों पर सुव्यवस्थित संवाद को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण राजनयिक और तकनीकी मंच के रूप में कार्य करेगा।

इस दौरान होने वाले विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक, चिह्नित और मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य व्यापार को बढ़ावा देना है, तो साथ ही निवेश, संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के अवसरों की पहचान करना भी है। इस चर्चा में जलवायु और बाजार जोखिमों के प्रति समुद्री खाद्य से जुड़ी मूल्य श्रृंखलाओं की सामर्थ्य को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार के रुझान और बाजार विविधीकरण के अवसर, मानक, प्रमाणन और नियामक सहयोग, इसकी प्रगति की पहचान की क्षमता, डिजिटल रिपोर्टिंग और अनुपालन प्रणाली, दीर्घकालिक और प्रतिबद्ध स्रोत निर्धारण, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण और उत्पाद संबंधी नवाचार, कोल्ड चेन से जुड़ी अवसंरचना, व्यवस्था संचालन तंत्र और बंदरगाह संपर्क, समुद्री व्यापार संबंधी मूल्य श्रृंखला में वित्तपोषण, साझेदारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी और मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि में डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन शामिल हैं।

इन विचार-विमर्शों में उभरते वैश्विक बाजार में तेजी से आ रहे बदलावों पर भी प्रकाश डाला जाएगा जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले, प्रमाणित और दीर्घकालिक स्रोतों से प्राप्त समुद्री खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशिया में मत्स्य पालन आधारित प्रोटीन की बढ़ती खपत, और पकाने के लिए तैयार, खाने के लिए तैयार तथा औषधीय और पोषण के स्तर वाले समुद्री उत्पादों सहित प्रीमियम उत्पाद श्रेणियों का विस्तार शामिल हैं। ये रुझान भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को बढ़ाकर, मूल्यवर्धित प्रसंस्करण पर अधिक ध्यान केंद्रित करके, प्रजातियों में विविधता लाकर, और मत्स्य पालन, प्रसंस्करण क्षमता और मजबूत निर्यातक आधार में प्रतिस्पर्धी शक्तियों का लाभ उठाकर देश की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।

सम्मेलन के परिणामों से खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, मत्स्य पालन संबंधी मूल्य श्रृंखलाओं में आजीविका में सुधार करने और स्थिरता, सामर्थ्य तथा समावेशी विकास के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी): भारतीय रेल के माध्यम से क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा

एक स्टेशन एक उत्पाद 2,000 से अधिक रेलवे स्टेशनों तक विस्तारित, 1.32 लाख कारीगरों को सशक्त बनाया गया और लाखों यात्रियों तक प्रत्येक्ष बाजार पहुंच के माध्यम से भारत की पारंपरिक शिल्पकलाओं को पुनर्जीवित किया गया

(जीएनएस)।

भारतीय रेल की 'एक स्टेशन एक उत्पाद' (ओएसओपी) स्कीम स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त मंच के रूप में उभरी है। यह पूरे देश में जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को भारत की समृद्ध क्षेत्रीय विविधता के जीवंत प्रदर्शन केंद्रों में बदलना है।

तेनकासी जं. रेलवे स्टेशन, तमिलनाडु

स्थानीय विरासत को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ एकीकृत करके, ओएसओपी न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाता है बल्कि समावेशी आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है।

तेनकासी जं. रेलवे स्टेशन, तमिलनाडु

19 जनवरी 2026 तक, 2,002 स्टेशनों पर ओएसओपी (एक स्टेशन एक उत्पाद) आउटलेट स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से कुल 2,326 आउटलेट कार्यरत हैं। ये आउटलेट हजारों स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और छोटे उत्पादकों के लिए आजीविका का स्रोत बन गए हैं, जिनका अब प्रतिदिन लाखों यात्रियों से सीधा संपर्क है। इसके अतिरिक्त, 2022 में ओएसओपी की शुरूआत के बाद से, इस पहल ने पूरे भारत में 1.32 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक अवसर सृजित किए हैं।

आंकड़ों के अतिरिक्त, ओएसओपी उन पारंपरिक शिल्पों और क्षेत्रीय विशिष्टताओं को पुनर्जीवित करने में मदद कर रहा है जो कभी लुप्त हो रही थीं। पूर्वोत्तर में हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तनों और बांस की कलाकृतियों से लेकर अन्य क्षेत्रों में मसालों, हथकरघा उत्पादों और स्थानीय मिठाइयों तक, ये उत्पाद यात्रियों को प्रत्येक क्षेत्र का सारतत्व प्रदान करते हैं।

वाणिज्य के साथ संस्कृति को समेकित करके, भारतीय रेल ने स्टेशनों को स्थानीय उद्यम के केंद्रों में बदल दिया है। 'एक स्टेशन एक उत्पाद' पहल "वोकल फॉर लोकल" का एक सच्चा उदाहरण है, जो समुदायों को सशक्त बनाने के साथ-साथ देश में यात्रियों के यात्रा अनुभव को समृद्ध करती है।

एपीडा ने असम से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जैविक उत्पाद सम्मेलन-सह-खरीदार-विक्रेता बैठक का आयोजन किया

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में 30 से अधिक निर्यातकों, 9 आयातकों और 50 विदेशी मुद्रा उत्पादक कंपनियों ने भाग लिया

प्रविष्टि तिथिः 20 खअठ 2026 12:53ढट ८ ढक्ह ऊ'

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी में एक जैविक सम्मेलन-सह-खरीदार-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य कृषि-निर्यात संबंधों को सुदृढ़. करना और असम के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार करना था।

इस सम्मेलन में असम के 30 से अधिक निर्यातकों, 9 आयातकों और लगभग 50 किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) ने भाग लिया। क्रेता-विक्रेता बैठक ने व्यापारिक संबंधों के लिए एक संरचित मंच प्रदान किया, जिससे हितधारकों को व्यापार के अवसरों का पता लगाने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने में मदद मिली।

असम अपनी समृद्ध कृषि-जलवायु विविधता के साथ निर्यात की अपार संभावनाओं वाली कई वस्तुओं का उत्पादन करता है। असम जोहा चावल और विभिन्न गैर-बासमती विशेष चावल किस्मों के अतिरिक्त, केला, अनानास, संतरा, असम नींबू, जैविक अदरक, हल्दी, काली मिर्च जैसे फल और सब्जियां, साथ ही

बागवानी और अन्य जैविक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला, वैश्विक कृषि बाजारों में राज्य की उपस्थिति का विस्तार करने के मजबूत अवसर प्रदान करती है।

सम्मेलन में जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) के आठवें संस्करण पर एक जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें नियामक ढांचा और लेबलिंग संबंधी आवश्यकताएं शामिल थीं। इस सत्र का उद्देश्य निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान उत्पादक संगठनों और उद्यमियों के बीच जागरूकता बढ़ाना था ताकि अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता और प्रमाणन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। क्रेता-विक्रेता सम्मेलन ने उत्पादकों, निर्यातकों और खरीदारों के बीच प्रत्यक्ष संवाद को सुगम बनाया, जिससे नए व्यापारिक साझेदारियों के विकास में सहायता मिली।

असम सरकार के कृषि, बागवानी और उत्पाद शुल्क मंत्री श्री अतुल बोरा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम और पूर्वोत्तर में उच्च गुणवत्ता वाले, जैविक रूप से उगाए गए कृषि और बागवानी उत्पादों का समृद्ध भंडार है। इनमें जोहा चावल, विशेष चावल की किस्में, मसाले, फल और स्वदेशी उत्पाद शामिल हैं, जिनकी वैश्विक स्तर पर मजबूत मांग है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण, अवसंरचना और बाजार पहुंच में केंद्रित सहायता और एपीडा की निरंतर साझेदारी के साथ, राज्य क्षेत्रीय कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यात में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, यह किसानों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित कर रहा है।

असम सरकार की आयुक्त एवं सचिव-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती अरुणा राजोरिया, आईएएस ने कहा कि असम में जीआई टैग से प्रमाणित और जैविक रूप से उगाए गए अनूठे कृषि उत्पाद हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर प्रबल मांग है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एपेडा के साथ घनिष्ठ सहयोग से एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण और बाजार संबंधों को मजबूत करने से किसानों और उद्यमियों को टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

अपने संबोधन में, एपीडा के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव ने एपीडा की निर्यात प्रोत्साहन कार्यकलापों में असम सरकार के समन्वय और सहयोग की सराहना की। उन्होंने संशोधित राष्ट्रीय खाद्य नीति (एनपीओपी) में किसान-हितैषी प्रावधानों और ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित जैविक पारस्परिक मान्यता समझौतों के साथ-साथ ब्रिटेन, ओमान और ईएफटीए देशों के साथ हाल ही में अंतिम रूप दिए गए मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से जैविक उत्पादों के लिए विस्तारित बाजार पहुंच द्वारा समर्थित राज्य से कृषि, बागवानी और जैविक निर्यात की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

उद्घाटन सत्र में असम सरकार के कृषि, बागवानी और उत्पाद शुल्क मंत्री श्री अतुल बोरा उपस्थित थे और इसमें असम सरकार की आयुक्त एवं सचिव-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती अरुणा राजोरिया, आईएएस; एपीडा के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव और असम सरकार के कृषि निदेशक श्री उदय प्रवीण, आईएएस ने भाग लिया।

असम जैविक उत्पाद सम्मेलन-सह-खरीदार-विक्रेता बैठक, भारत के कृषि निर्यात विकास गाथा में क्षेत्रीय शक्तियों को एकीकृत करने के लिए एपीडा के निरंतर प्रयासों को दशार्ती है, साथ ही असम को उच्च मूल्य और टिकाऊ कृषि निर्यात में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करती है।

ऑपरेटिंग विभाग की टीम बनी डीआरएम कप-2026 चैम्पियन

वडोदरा मंडल की ऑपरेटिंग विभाग की टीम ने डीआरएम कप 2026 क्रिकेट टूनार्मेंट जीत लिया है। प्रतापनगर में माधव राव सिंधिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में ऑपरेटिंग विभाग की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग की टीम को 7 विकेट से हराकर डीआरएम कप पर कब्जा किया।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 08 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित इस टूनार्मेंट में वडोदरा मंडल के विभिन्न विभागों की कुल 16 टीमों ने खेल भावना के साथ भाग लिया।

प्रतियोगिता का फाइनल मैच विद्युत(ट्रैक्शन)विभाग एवं ऑपरेटिंग विभाग की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें ऑपरेटिंग विभाग की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और 'डीआरएम ट्रॉफी-2026' की चैम्पियन बनी।

वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक एवं वडोदरा मंडल खेलकूद संघ के अध्यक्ष श्री राजू भडके ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की और साथ ही टूनार्मेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मोमेंटो एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि रेल कर्मियों को अपनी ड्यूटी के साथ-साथ खेलकूद गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए, जिससे वे स्वस्थ और ऊजार्वान बने रहें।

इस प्रतियोगिता में सुरक्षा विभाग के श्री मीठाभाई को बेस्ट बॉलर एवं ऑपरेटिंग विभाग के श्री महेंद्र देसाई ने बेस्ट बैट्समैन का खिताब जीता। ऑपरेटिंग विभाग के श्री कार्तिक को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के मार्गदर्शन में वीडीएसए द्वारा इस टूनार्मेंट का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज धमीजा, वीडीएसए के सचिव श्री प्रदीप मीणा एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे।

233 साल पुरानी वाल्मीकि रामायण राम कथा संग्रहालय को भेंट की गई

(जीएनएस)।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक हस्तांतरण के तहत, तीन मूर्ति स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र को वाल्मीकि रामायण (तत्त्वदीपिका टीका सहित) की 233 वर्ष पुरानी संस्कृत की एक दुर्लभ पांडुलिपि सौंपी।

आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित और महेश्वर तीर्थ की शास्त्रीय टीका से युक्त यह पांडुलिपि संस्कृत (देवनागरी लिपि) में लिखी गई है। यह विक्रम संवत 1849 (1792 ईस्वी) की एक ऐतिहासिक महत्व की कृति है और रामायण की एक दुर्लभ सुरक्षित पाठ परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। इस संग्रह में महाकाव्य के पांच प्रमुख कांड बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और युद्धकांड शामिल हैं, जो इतिहास की कथात्मक और दार्शनिक गहराई को दशार्ते हैं।

पहले नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन को अस्थायी रूप से सौंपी गई पांडुलिपि को अब अयोध्या, उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को स्थायी रूप से उपहार में दिया गया है। यह महत्वपूर्ण कदम रामायण विरासत के वैश्विक केंद्र के रूप में संग्रहालय के विकास में सहायता करता है, जिससे आम जनता तक इसकी व्यापक पहुंच के साथ इसका संरक्षण सुनिश्चित होगा।

प्रो. वराखेड़ी ने कहा, "यह उपहार पवित्र अयोध्या नगरी में वाल्मीकि रामायण के गहन ज्ञान को अमरता प्रदान करेगा, जिससे विद्वानों, भक्तों और दुनिया भर के आगंतुकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित होगी।"

पीएमएमएल की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र ने कहा, 'वाल्मीकि रामायण की इस दुर्लभ पांडुलिपि का अयोध्या स्थित राम कथा संग्रहालय को दान राम भक्तों और अयोध्या स्थित मंदिर परिसर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।'

केंद्र सरकार ने उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया

लंबित टोल बकाया होने पर वाहन हस्तांतरण, फिटनेस नवीनीकरण और परमिट के लिए एनओसी नहीं मिलेगी

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान के अनुपालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ' केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026' अधिसूचित किया है। इसके माध्यम से 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989' में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों का लक्ष्य उपयोगकर्ता शुल्क अनुपालन में सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की दक्षता बढ़ाना और राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क चोरी को हतोत्साहित करना है।

संशोधित नियमों के तहत 'अदा न किए गए उपयोगकर्ता शुल्क' की एक नई परिभाषा जोड़ी की गई है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड के उपयोग के लिए देय उपयोगकर्ता शुल्क को संदर्भित करती है, जहां इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) प्रणाली ने वाहन के उस खंड से गुजरने को दर्ज किया है, किंतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार लागू शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है।

संशोधनों के अनुसार, अदा न किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान को वाहन संबंधी सेवाओं से जोड़ा गया है। प्रावधानों के अनुसार, स्वामित्व हस्तांतरण या एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के ट्रांसफर के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि बकाया उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान नहीं हो जाता। इसके अलावा, वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण या उसे जारी करना तब तक नहीं होगा, जब तक बकाया उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान नहीं हो जाता। राष्ट्रीय परमिट चाहने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए संशोधित नियमों के अनुसार यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वाहन पर कोई भी बकाया उपयोगकर्ता शुल्क न हो।

'फॉर्म 28' में भी इसी के अनुरूप बदलाव किए गए हैं, जिसके अनुसार अब आवेदकों को टोल प्लाजा पर वाहन के विरुद्ध किसी बकाया उपयोगकर्ता शुल्क की मांग लंबित होने की जानकारी और साथ ही संबंधित विवरण भी देना होगा। डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हुए नियमों में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 'फॉर्म 28' के प्रासंगिक भागों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने की सुविधा भी दी गई है। 'फॉर्म 28' अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए एक आवेदन है, जो वाहन के स्वामित्व को किसी अन्य राज्य या जिले में ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वाहन पर कोई कर, चालान या कानूनी मामला लंबित नहीं है। ये संशोधन मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) प्रणाली के लागू होने के बाद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह में भी सहायक होंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर बाधा रहित टोलिंग की सुविधा भी प्रदान करेंगे।

11 जुलाई 2025 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मसौदा नियमों के प्रकाशित होने के बाद ये संशोधन जारी किए गए हैं, जिसमें हितधारकों और आम जनता से सुझाव मांगे गए थे। मसौदा अधिसूचना की प्रतियां 14 जुलाई 2025 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गईं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने संशोधित नियमों को अंतिम रूप दिया और अधिसूचित किया।

ये संशोधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के सतत विकास और रखरखाव के लिए पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित टोलिंग प्रणालियों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

भारत के अंतदेर्शीय जलमार्गों के विकास के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करेगा

आईडब्ल्यूडीसी 3.0 भारत के अंतदेर्शीय जलमार्गों के विकास के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करेगा

ब्रह्मपुत्र नदी हरित परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है, आईडब्ल्यूडीसी 3.0 का अगला चरण असम के लिए निर्धारित किया जा रहा है

(जीएनएस)।

अंतदेर्शीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) की तीसरी बैठक 23 जनवरी, 2026 को कोच्चि, केरल में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य अंतदेर्शीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र की उपलब्धियों को उजागर करना और इसके भविष्य के दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करना है।

दिनभर चलने वाले इस सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सरबानंदा सोनोवाल करेंगे और इसमें बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्री भी उपस्थित होंगे।

बैठक के दौरान, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री विभिन्न राज्यों में अंतदेर्शीय जल परिवहन को और विकसित करने के लिए नई पहलों का शुभारंभ करेंगे। अंतदेर्शीय जल परिवहन परियोजनाओं के लिए केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करने हेतु कई राज्य सहायता समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है।

आईडब्ल्यूडीसी 3.0 के एजेंडे में एक सुदृढ़ शहरी जल परिवहन प्रणाली का निर्माण, माल परिवहन की दक्षता बढ़ाना, यात्री परिवहन के लिए हरित जलयानों को बढ़ावा देना, नदी क्रूज पर्यटन को आगे बढ़ाना और डिजिटल एवं टिकाऊ प्रथाओं को लागू करने पर सत्र शामिल हैं। बैठक में अंतदेर्शीय जलमार्गों के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा भी की जाएगी और राज्यों द्वारा चल रही और प्रस्तावित अंतदेर्शीय जल परिवहन परियोजनाओं से संबंधित उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जाएगा।

भारत में अंतदेर्शीय जलमार्गों का एक व्यापक जाल है, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष 14 करोड़ टन से अधिक माल का परिवहन होता है। यह ईंधन-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का एक साधन है। अंतदेर्शीय जलमार्ग रेल और सड़क नेटवर्क पर बढ़ते दबाव को कम करते हैं और रोल-ऑन-रोल-ऑफ (रो-रो) वाहन परिवहन और नदी क्रूज पर्यटन जैसी पहलों को सुगम बनाते हैं। 23 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में फैले कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 32 वर्तमान में माल और यात्री परिवहन के लिए कार्यरत हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय अंतदेर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) इन जलमार्गों के विकास, रखरखाव और विनियमन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल ढुलाई 2013-14 में 18 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 145.84 मिलियन टन हो गया है, जबकि यात्री यातायात 2024-25 में बढ़कर 7.64 करोड़ हो गया है। 'जलवाहक' कार्गो प्रोत्साहन योजना जैसी परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से इस गति को और भी बल मिला है, जो माल ढुलाई करने वालों को सड़क और रेल मार्ग से जलमार्गों पर माल स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और 'जल समृद्धि' योजना, जो टर्मिनल विकास और संचालन में मजबूत निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देती है।

'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, अंतदेर्शीय जलमार्ग परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) एक सच्चा सहयोगात्मक राष्ट्रीय मंच बन गया है, जो नीति निमार्ताओं और विभिन्न राज्य सरकारों तथा संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को अंतदेर्शीय जलमार्गों को आकार देने के लिए एक साथ लाता है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सरबानंदा सोनोवाल ने आईडब्ल्यूडीसी को केंद्र-राज्य प्राथमिकताओं को संरेखित करने, नीतिगत इरादों को कार्रवाई योग्य परिणामों में बदलने और एक हरित, अधिक कुशल परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में रूपांतरित किया है। आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष सुनील पालीवाल ने कहा- 'अवसंरचना विकास को स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी के साथ जोड़कर परिषद, भारत की नदी विरासत को पुनर्जीवित कर रही है और माल और यात्रियों के लिए परिवहन के पसंदीदा साधन के रूप में अंतदेर्शीय जलमार्गों को पुनः स्थापित कर रही है। कोच्चि में, हमारा लक्ष्य 2024 में आईडब्ल्यूडीसी 1.0 और 2025 में आईडब्ल्यूडीसी 2.0 के बाद से हुई प्रगति को सुदृढ़ करना, परियोजना निष्पादन में तेजी लाना और राज्यों के साथ घनिष्ठ साझेदारी में हरित, प्रौद्योगिकी-संचालित अंतदेर्शीय जलमार्गों का विस्तार करना है।'

असम आईडब्ल्यूडीसी 3.0 में

जलमार्ग यातायात में लगातार वृद्धि इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) ने पिछले दो वर्षों में नीतिगत निर्णयों को ठोस परिणामों में सफलतापूर्वक बदला है। पांडु और जोगीघोपा में बहुस्तरीय टर्मिनलों, धुबरी और बोगीबील में स्थायी टर्मिनलों, कई फ्लोटिंग टर्मिनलों और बांग्लादेश सीमा से सादिया तक सुनिश्चित गहराई रखरखाव के साथ पूर्णतः चालू राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (ब्रह्मपुत्र) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत परिवहन को नया रूप दे रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम के अंतदेर्शीय जलमार्गों के 98% से अधिक माल का संचालन करता है, जिसमें वाहन, बड़े आकार के माल और निर्माण सामग्री शामिल हैं।

ग्रेस सिटी आवासीय परियोजना का हुआ भूमि पूजन

टावर बी में आधुनिक व सुविधायुक्त फ्लैट होंगे उपलब्ध। निदेशक टी एन सिंह

एसबीएम, कानपुर

ग्रेस सिटी आवासीय परियोजना के तहत ग्रेसलैंड के टावर-ए की बुकिंग पूर्ण होने के बाद टावर बी का विधिवत भूमि पूजन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर ग्रेसलैंड के निदेशक टीएन सिंह और रोहित रघुवंशी ने पुरोहित के द्वारा वैदिक मंत्रोचारण का पूजन किया। जानकारी देते हुए निदेशक टी एन सिंह ने बताया कि टावर बी में आधुनिक व सुविधायुक्त फ्लैट उपलब्ध होंगे, जिन्हें ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान

में रखते हुए डिजाइन किया गया है। वहीं रोहित रघुवंशी ने बताया कि इस परियोजना में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली पर विशेष ध्यान दिया गया है। परियोजना की आंतरिक सड़कों की चौड़ाई 80 फीट रखी गई है। भूमि पूजन में बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय मौजूद रहे।

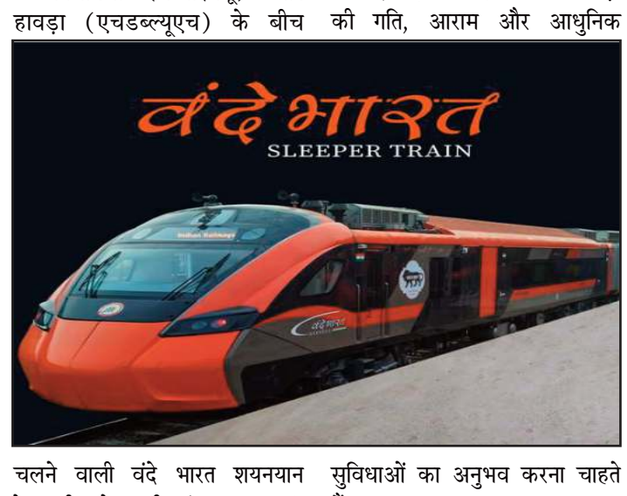

वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई है

टिकट काउंटर खुलते ही कुछ ही घंटों में इस रेलगाड़ी की पहले दिन की यात्रा के सभी टिकट बुक हुए

(जीएनएस)।

कामाख्या (केवाईक्यू) और हावड़ा (एचडब्ल्यूएच) के बीच

चलने वाली वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी (रेलगाड़ी संख्या 27576) की पहली व्यावसायिक यात्रा को यात्रियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। पीआरएस और अन्य साइटों के माध्यम से टिकट बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर सभी सीटें बुक हो गईं। सीटों की इतनी जल्दी बुकिंग होना यात्रियों की उस उत्सुकता को स्पष्ट रूप से दशार्ता है जिसके चलते वे 17 जनवरी, 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी की गति, आराम और आधुनिक सुविधाओं का अनुभव करना चाहते हैं।

यह रेलगाड़ी 22 जनवरी 2026 से कामाख्या से और 23 जनवरी 2026 से हावड़ा से अपनी पहली व्यावसायिक यात्रा शुरू करेगी। इस नई रेल सेवा के लिए टिकट बुकिंग 19 जनवरी 2026 को सुबह 8:00 बजे शुरू हुई। 24 घंटे से भी कम समय में सभी श्रेणियों के टिकट पूरी तरह बिक गए, जो इस प्रीमियम सेमी-हाई-स्पीड रेल सेवा के प्रति जनता के जबरदस्त उत्साह को दशार्ता है।

अपनी पहली ही व्यावसायिक यात्रा में मिली इस शानदार प्रतिक्रिया से यात्रियों की तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक रेल यात्रा विकल्पों के प्रति बढ़ती रुचि स्पष्ट दिखाई देती है। कामाख्या-हावड़ा वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी से पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है, जो आधुनिक सुविधाएं, बेहतर यात्रा समय और विश्व स्तरीय रात्रिकालीन यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी।

कुछ ही घंटों में पूरी तरह बुक हो जाने की स्थिति भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जा रही आधुनिक रेल सेवाओं के प्रति यात्रियों के विश्वास और उत्साह का एक मजबूत प्रमाण है, जो इस क्षेत्र के लिए प्रीमियम रेल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ती है।

लखनऊः राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने विधानसभाओं को अधिक सक्षम बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका पर बल दिया

(जीएनएस)। राज्यसभा के माननीय उपसभापति हरिवंश ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (एआईपीओसी) के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों के पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए विधानसभाओं को अधिक सक्षम बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका पर बल दिया और साथ ही इस तकनीक को सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न आवश्यक कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने संसद में एआई के उपयोग के विभिन्न व्यावहारिक उदाहरणों और तार-तरीकों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं और संसद के बीच अधिक तालमेल का

आह्वान किया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विधानसभाओं के संस्थागत ज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए किया जा सके। उन्होंने नीतिगत सूचनाओं के सामंजस्यपूर्ण समन्वय और सुलभता के दृष्टिकोण पर बल देते हुए कहा, 'विधानमंडल उन सभी आधिकारिक नीतिगत दस्तावेजों के संरक्षक होते हैं जिनमें कानून, बजट आदि पर विभिन्न बहसें शामिल हैं।

ये दस्तावेज सदन में पेश किए जाने पर सदन का हिस्सा बन जाते हैं। यह जानकारी अक्सर विभिन्न मंत्रालयों में बिखरी रहती है।

संसद और राज्य विधानसभाएं एआई का उपयोग करके ऐसे मंच का निर्माण कर सकती हैं जिससे ये सभी के लिए आसानी से सुलभ हो सकें। इससे इन संवैधानिक संस्थाओं को ज्ञान के केंद्र के रूप में निर्मित करने को बढ़ावा मिलेगा।'

पीडीयूएनएएसएस ने ₹कानूनी प्रबंधन और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016₹ पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया

(जीएनएस)। नई दिल्ली स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीयूएनएएसएस) ने कल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधिकारियों के लिए 'कानूनी प्रबंधन और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016) पर एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 19 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आईबीसी ढांचे के तहत उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों और दिवाला संबंधी मामलों से निपटने में ईपीएफओ अधिकारियों की कानूनी और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है।

उद्घाटन सत्र को पीडीयूएनएएसएस के निदेशक श्री कुमार रोहित, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के महाप्रबंधक श्री राजेश तिवारी, पीडीयूएनएएसएस के मुख्य शिक्षण अधिकारी श्री रिजवान उद्दीन तथा

आरपीएफसी-आई एवं पाठ्यक्रम निदेशक श्री संजय कुमार राय ने संबोधित किया।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पीडीयूएनएएसएस के निदेशक श्री कुमार रोहित ने कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ने भारत के कानूनी और आर्थिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है।

उन्होंने कहा कि ईपीएफओ जैसे वैधानिक प्राधिकरणों को अधिस्थगन प्रावधानों, भविष्य निधि बकाया की प्राथमिकता और उनका निपटारा, मूल्यांकन बनाम वसूली से जुड़े मुद्दों और आईबीसी व्यवस्था के तहत न्याय निर्णयन अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व से संबंधित जटिल कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

निदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि दिवाला संबंधी न्यायशास्त्र निरंतर विकसित हो रहा है और इसके लिए ईपीएफओ अधिकारियों को कानूनी रूप से अद्यतन, प्रक्रियात्मक रूप से सुसंगत और संस्थागत रूप से सरिक्षित रहने की आवश्यक है।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ आईबीसी के वैधानिक ढांचे का अनुपालन करने के लिए दिवाला संबंधी मामलों का प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है।

खेल मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने लद्दाख को खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेजबानी करने की क्षमता का प्रदर्शन करने पर बधाई दी

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने केआईडब्ल्यूजी 2026 के लेह चरण का उद्घाटन किया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की खेल संबंधी दूरदर्शिता की सराहना की

पहली बार आइस स्केटिंग कार्यक्रम में फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया

इसमें खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों सहित लगभग 1060 लोग हिस्सा लेंगे

जिसका पहला चरण 26 जनवरी को समाप्त होगा

(जीएनएस)। जम्मू-कश्मीर में लद्दाख के नवांग दोरजे स्टोबदान (एनडीएस) स्टेडियम में मंगलवार को खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण का शुभारंभ हुआ। शीतकालीन खेलों के लद्दाख चरण में स्केटिंग और हॉकी जैसे बर्फीले खेल शामिल हैं जिसका

समापन 26 जनवरी को होगा। यह तीसरा बार है जब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शीतकालीन खेलों की मेजबानी कर रहा है। शीतकालीन खेलों का बर्फीला चरण इस वर्ष के अंत में जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा।

रंगारंग उद्घाटन समारोह में, जिसमें पारंपरिक संगीत एवं नृत्य तथा आर्मी इलेवन एवं केंद्र शासित प्रदेश के बीच एक प्रदर्शनी आइस हॉकी मैच का आयोजन शामिल था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल श्री कवींदर गुप्ता ने किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का पहला चरण लद्दाख के युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है। खेलों का संचालन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता राष्ट्रीय खेल संवर्धन निकायों/संघों द्वारा प्रदान की जाती है जो हिम खेलों का प्रबंधन करते हैं।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने लद्दाख को संबोधित करते हुए अपने एक संदेश में कहा, "मैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को एक बार फिर सफलतापूर्वक खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करने और इसे आत्मविश्वास एवं क्षमता के साथ प्रदर्शित करने के लिए बधाई देता हूं कि भारत का शीतकालीन खेलों का भविष्य हिमालय से भारत के शीतकालीन खेलों का भविष्य हिमालय से शुरू होकर आगे की ओर बढ़ रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने विकसित भारत कृषि यंग लीडर्स 2026 के साथ वर्चुअल संवाद किया

वर्चुअल संवाद के माध्यम से युवा कृषि लीडर्स को राष्ट्रीय स्तर पर नए विचार साझा करने और उन्हें लागू करने का एक नया अवसर प्राप्त होगा – श्री शिवराज सिंह चौहान

युवा उनके लिए केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि भारतीय कृषि के रूपांतरण हेतु उनकी प्रतिभा का उपयोग करने का यह एक बड़ा अवसर - केंद्रीय कृषि मंत्री

प्रविष्टि तिथिः 20 खअठ 2026 8:36ढट ु८ ढक्ह ऊै

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत यंग लीडर्स 2026 के प्रतिभागियों के साथ आज एक वर्चुअल संवाद बैठक की। यह बैठक 12 जनवरी 2026 को भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के क्रम में आयोजित की गई।

इस अवसर पर डॉ.एम. एल.

जाट, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, आईसीएआर ने केंद्रीय मंत्री तथा युवाओं का स्वागत किया तथा कहा कि युवा भविष्य के नवोन्मेषक, उद्यमी और नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होंगे। इस वर्चुअल संवाद के माध्यम से युवा कृषि लीडर्स को राष्ट्रीय स्तर पर नए विचार साझा करने और उन्हें लागू करने का एक नया अवसर प्राप्त होगा।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवा केवल उनके लिए विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि भारतीय कृषि के रूपांतरण हेतु उनकी प्रतिभा का उपयोग करने का यह एक बड़ा अवसर है। उन्होंने विचारों और नवाचारों की भूमिका पर बल देते हुए कहा कि इनके माध्यम से खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, किसानों की आय में वृद्धि तथा कृषि को अधिक किसान-हितैषी बनाया जा सकता है।

युवाओं से दालों और तिलहनों के आयात को कम करने, कम लागत वाली खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों, कृषि यंत्रीकरण, तथा उर्वरक सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए डिजिटल अवसंरचना के प्रभावी उपयोग जैसे विषयों पर नए और व्यावहारिक विचार देने का आग्रह किया। उन्होंने देश स्तर पर एक साझा मंच से जुड़कर छोटे और सीमांत किसानों के लिए नवाचारी मॉडल विकसित करने हेतु युवाओं को प्रेरित किया।

खान मंत्रालय के सचिव श्री पीयूष गोयल 21 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 65वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक को संबोधित करेंगे

भूविज्ञान को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालते हुए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 65वीं सीजीपीबी बैठक में अपने आगामी वार्षिक कार्यक्रम के अनावरण के साथ भविष्य की भूवैज्ञानिक पहलों की रूपरेखा तैयार करेगा

(जीएनएस)। खान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) 21 जनवरी 2026 को एपी शिंदे संगोष्ठी हॉल, आईसीएआर, पूसा, नई दिल्ली में 65वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड (सीजीपीबी) की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उद्योग, शिक्षा जगत और खनन क्षेत्रों के प्रमुख हितधारक भूवैज्ञानिक- प्रगति, खनिज अन्वेषण रणनीतियों और स्वच्छ ऊर्जा, भू-खतरों एवं सतत विकास सहित चुनौतियों के समाधान पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ एक मंच पर होंगे।

केंद्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड (सीजीपीबी) खान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके अंतर्गत जीएसआई के वार्षिक क्षेत्र सत्र कार्यक्रम (एफएसपी) पर चर्चा की जाती है और कार्यों के दोहराव से बचा जाता है। सीजीपीबी के सदस्य और अन्य हितधारक जैसे राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य सरकार की खनिज अन्वेषण एजेंसियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी उद्यमी जीएसआई के साथ सहयोगात्मक कार्य के लिए अपने अनुरोध प्रस्तुत करते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और सदस्यों एवं हितधारकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के महत्व और तात्कालिकता के आधार पर, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, अन्वेषण, अनुसंधान एवं विकास, सामाजिक परियोजनाओं के लिए बहुविषयक कार्य तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए जीएसआई के वार्षिक कार्यक्रम को सीजीपीबी की शीर्ष स्तरीय बैठकों में उचित चर्चा और विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाता है।

खान मंत्रालय के सचिव श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में 65वीं सीजीपीबी बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में जीएसआई के महानिदेशक श्री असित साहा और खान मंत्रालय के अपर सचिव श्री संजय लोहिया के साथ-साथ खान मंत्रालय, जीएसआई, राज्य भूवैज्ञानिक विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी अन्वेषण/खनन कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

बैठक में होने वाली चर्चा देश के खनिज क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं पर केंद्रित होगी, जिनमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

लिथियम, आरईई, ग्रेफाइट, पीजीई, वैनेडियम, स्कैंडियम, सीजियम आदि जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण, ऊर्जा परिवर्तन और आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जाना।

एआई/एमएल आधारित डेटा एकीकरण, भूभौतिकीय सर्वेक्षण, हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, डीप ड्रिलिंग और खनिज प्रणाली अध्ययन जैसे आधुनिक अन्वेषण उपकरणों को अपनाना।

राष्ट्रीय संसाधनों को अनुकूलित करने, दोहराव को कम करने और अन्वेषण से नीलामी के लिए तैयार ब्लॉकों में संक्रमण को गति देने के लिए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए, पूर्व-प्रतिस्पर्धी डेटा साझाकरण और सहयोगात्मक अन्वेषण मॉडल।

विशेष रूप से हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भूस्खलन खतरे के क्षेत्र निर्धारण और ढलान स्थिरता अध्ययन।

इस बैठक में भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की 1,068 परियोजनाओं के जीएसआई का वार्षिक कार्यक्रम (वित्तीय सर्वेक्षण वर्ष 2026-27) प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें खनिज अन्वेषण पर विशेष बल दिया गया है। कार्यक्रम में नवाचार और स्थिरता पर जोर देने के साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों, कार्बन पृथक्करण अध्ययन, अपतटीय अन्वेषण और जनहित भूविज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। बैठक में गणमान्यजनों द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सामरिक एवं महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में जीएसआई की गतिविधियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

'तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई', ST कर्मचारी को जामिया प्रोफेसर ने पीटा, जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप

(जीएनएस)। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। अनुसूचित जनजाति (ऌ) के कर्मचारी राम फूल मीणा ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रियाजुद्दीन पर जातिगत दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पॉलिटेक्निक विभाग में अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर तैनात मीणा ने अपनी लिखित शिकायत एसीपी सरिता विहार को सौंपी है।

शिकायत के अनुसार, यह विवाद डॉ. रियाजुद्दीन के खिलाफ छात्रों से दुर्व्यवहार से जुड़े एक वायरल वीडियो के बाद शुरू हुआ। राम फूल मीणा का उस शिकायत से सीधा संबंध न होने पर भी उन्हें कथित तौर पर निशाना बनाया गया। मीणा ने आरोप लगाया कि 13 जनवरी 2026 को प्रोफेसर उनके डेस्क पर आए और उन्हें आपत्तिजनक व अभद्र शब्द कहे।

मुसलमानों के संस्थान में रहकर जुर्रत कैसे की?

मामला 16 जनवरी 2026 को तब और गंभीर हुआ, जब डॉ. रियाजुद्दीन ने मीणा के ऑफिस में कथित तौर पर हमला किया। शिकायत में मीणा ने बताया कि प्रोफेसर ने जातिसूचक गालियां देते हुए कहा, "तुम्हारी औकात कैसे हुई कि तुम मेरे खिलाफ शिकायत करो? तुम आदिवासी जंगली हो, मुसलमानों के इदारे (संस्थान) में रहकर मेरे खिलाफ शिकायत करने की जुर्रत कैसे की?"

"काफिर" कहकर अपमानित किया

इस हमले में मीणा के होंठ फट गए और आँख के नीचे सूजन आ गई, जिसका इलाज उन्हें विश्वविद्यालय के अंसारी स्वास्थ्य केंद्र में कराना पड़ा। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया है कि हिंदू और आदिवासी पहचान के कारण उन्हें परिसर में कई लोगों द्वारा "काफिर" कहकर लक्षित व अपमानित किया जा रहा है।

मामला दर्ज होते ही कार्रवाई के बजाय कर दिया तबादला

हैरान करने वाली बात यह रही कि रजिस्ट्रार कार्यालय में मीणा की शिकायत दर्ज होती ही, उसी दिन यानी 16 जनवरी को उनका तबादला आदेश जारी कर दिया गया। मीणा ने इस कदम को "दंडात्मक कार्रवाई और सच दबाने की कोशिश" बताया है। इस बीच, दिल्ली पुलिस सूत्रों ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए जांच जारी होने की जानकारी दी है।

क्लासरूम में छात्र को लातों से मारते हुए वीडियो हुआ वायरल?

इधर, डॉ. रियाजुद्दीन का एक अन्य वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वे क्लासरूम में एक छात्र को लात मारते दिख रहे हैं। इस घटना को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। राम फूल मीणा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और

केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने बीएसएनएल के तीसरी तिमाही के प्रदर्शन की समीक्षा की

श्री सिंधिया ने सेवा की गुणवत्ता, मोबाइल ग्राहक आधार और प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया

(जीएनएस)। केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज नई दिल्ली में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की तीसरी तिमाही (2025-26) की रणनीतिक समीक्षा और योजना बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, दूरसंचार सचिव श्री अमित अग्रवाल, अपर सचिव श्री गुलजार नटराजन, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के वरिष्ठ अधिकारी, बीएसएनएल के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री ए. रॉबर्ट जे. रवि, निदेशक मंडल और देश भर के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) उपस्थित थे।

नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में बीएसएनएल की तीसरी तिमाही के प्रदर्शन और प्रमुख सेवा गुणवत्ता मानकों की व्यापक समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने बीएसएनएल के मोबाइल ग्राहक आधार और एआरपीयू बढ़ाने, सेवा गुणवत्ता मापदंडों में सुधार तथा राजस्व लक्ष्यों को प्राप्ति की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक के दौरान सभी सेवा क्षेत्रों में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की सर्किल-वार विस्तृत समीक्षा की गई। अलग-अलग सर्किलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना और कमियों को दूर करना था।

मोबाइल ग्राहक आधार की वृद्धि और मोबाइल खंड में बीएसएनएल की उपस्थिति को मजबूत करने की पहलों पर विशेष जोर दिया गया। परिचालन प्रगति पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां कुछ सर्किलों ने मोबाइल ग्राहक आधार में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है, वहीं अन्य सर्किलों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है।

केंद्रीय मंत्री ने उल्लेख किया कि मोबाइल प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में तिमाही-दर-तिमाही सुधार हुआ है। जिन सर्किलों में एआरपीयू स्थिर था, उनसे अपने एआरपीयू को बढ़ाने का आग्रह किया गया। बेहतर सेवा पेशकश, ग्राहक बनाए रखने की रणनीतियों और मूल्य वर्धित सेवाओं के माध्यम से एआरपीयू बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई।

केंद्रीय मंत्री ने सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) के प्रमुख मानकों- जैसे मोबाइल नेटवर्क उपलब्धता और औसत मरम्मत समय (एमटीटीआर)-की समीक्षा की। केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व), कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कोलकाता, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे सर्किलों को मोबाइल बीटीएस एमटीटीआर में तिमाही-दर-तिमाही उल्लेखनीय सुधार के साथ अग्रणी सर्किलों के रूप में चिन्हित किया गया। सभी सर्किलों को नेटवर्क विश्वसनीयता में लगातार सुधार करने, डाउनटाइम कम करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए दोषों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।

उद्यम व्यवसाय खंड में केंद्रीय मंत्री ने उद्यम व्यवसाय के अधिग्रहण और वृद्धि में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पांच 'स्टार परफॉर्मिंग' सर्कलों - कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (पश्चिम)-को बधाई दी।

चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के लिए राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सर्कल-वार योजनाएं और रणनीतियां प्रस्तुत की गईं और उन पर चर्चा की गई।

केंद्रीय मंत्री ने सभी मुख्य महाप्रबंधकों (सीजीएम) को निर्देश दिया कि वे निरंतर ग्राहक जोड़ने और सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करें।

केंद्रीय मंत्री ने इस वित्तवर्ष की अंतिम तिमाही में सर्किलों के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने और उनसे आगे निकलने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ सर्कल स्तर पर केंद्रित निष्पादन, जवाबदेही और प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए बैठक का समापन किया।

भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप सुदर्शिनी लोकायन 26 के लिए रवाना

दस महीने लंबे ट्रांसओशनिक अभियान – लोकायन 26 को दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि से हरी झंडी दिखाई गई

आईएनएस सुदर्शिनी भारत की समुद्री विरासत को दर्शाते हुए एक ऐतिहासिक वैश्विक यात्रा पर निकला

वसुधैव कुटुंबकम की भावना और महासागर के विजन के साथ महासागरों में सहयोग और विश्वास का सेतु

(जीएनएस)। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने 20 जनवरी, 2026 को कोच्चि के नौसैनिक बेस से आईएनएस सुदर्शिनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एक लंबी दूरी की नौकायन यात्रा - लोकायन 26 की शुरुआत का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक यात्रा भारत के समुद्री प्रयासों का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो वैश्विक समुद्री गतिविधियों में देश की प्रमुखता और भारतीय नौसेना की पेशेवर प्रशिक्षण और समुद्री नौकायन अभियान में उत्कृष्टता के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाती करती है।

झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए आयोजित समारोह में वरिष्ठ अधिकारी, नौसेना समुदाय के उत्साही

सदस्य, स्कूली बच्चे, जहाज के चालक दल के परिवार के सदस्य और मीडियाकर्मी मौजूद थे। इस अवसर पर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण ने लोकायन 26 पट्टिका का अनावरण किया। चालक दल के साथ बातचीत के दौरान, उन्होंने भारत के "एम्बेसडर" के रूप में जहाज की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा महासागरों और सीमाओं से परे है, जो दुनिया भर में "दोस्ती के सेतु" बनाती है। पारंपरिक विदाई समारोह में, तीन मस्तूलों वाले जहाज ने नौसेना बैंड की जोशीली धुन के साथ अपने पाल फहराए।

दस महीने की इस तैनाती के दौरान, आईएनएस सुदर्शिनी लगभग 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा करेगा, और 13 देशों के 18 बंदरगाहों का दौरा करेगा। इस यात्रा की मुख्य बातों में से एक फ्रांस में एस्केल ए सेट में जहाज की भागीदारी है। मार्च-अप्रैल 2026 में यूरोप के प्रमुख समुद्री त्योहारों में से एक में अपनी शुरुआत करते हुए, आईएनएस सुदर्शिनी भूमध्य सागर में प्रसिद्ध बड़े जहाजों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा, जुलाई 2026 में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, जहाज न्यूयॉर्क में अंतरराष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स के दौरान एक भव्य अंतरराष्ट्रीय बेड़े यानी सेल 250 में शामिल होगा।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित, आईएनएस सुदर्शिनी भारतीय नौसेना का 54-मीटर का नौकायन प्रशिक्षण जहाज है जो 20 पालों से सुसज्जित है। इसका पाल क्षेत्र 1,000 वर्ग मीटर से अधिक है। यह जहाज समुद्री प्रशिक्षुओं और अधिकारी कैडेटों को हवा तथा लहरों के मार्गदर्शन में नाविकता और नेविगेशन की कलातीत कला विकसित करने के लिए अद्वितीय मंच प्रदान करता है। जैसे-जैसे आईएनएस सुदर्शिनी प्राचीन व्यापार मार्गों और आधुनिक समुद्री रास्तों पर आगे बढ़ता है, वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साथ लेकर चलता है, और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और समग्र विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) के विजन को आगे बढ़ाता है।